



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 172]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 23, 1977/ वैशाख 3, 1899

No. 172]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 23, 1977/VAISAKHA 3, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 23rd April 1977

S.O 298(E)/18FB/IDRA/77.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No S O 250(E)/18FB/IDRA/73, dated the 28th April, 1973 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (85 of 1951), declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said Order (other than those relating to the liabilities relating to the banks and financial institutions) to which the industrial undertaking known as M/s Hindustan Tractors Limited, Vadodara (formerly Baroda) or the company owning such industrial undertaking is a party or which may be applicable to such industrial undertaking or company shall remain suspended for a period of one year from the date of issue of the said Order and that all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period.

And whereas by the Orders of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 261(E)/18FB/IDRA/74, dated the 24th April, 1974, in the late Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development No. S.O. 173(E)/18FB/IDRA/75, dated the 9th April, 1975 and No. S.O. 309(E)/18FB/IDRA/76, dated the 22nd April, 1976 the said Order was extended for the period upto and inclusive of the 25th of April, 1977;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period upto and inclusive of the 11th of March, 1978;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) the Central Government hereby extends the duration of the said Order for a further period upto and inclusive of the 11th of March, 1978.

[No. F 4/1/73-CUC.]

A.K. GHOSH, Addl. Secy.

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1977

का० आ० 298(अ)/18 एफ० बी० आई० डी० आर० ए० 8/77 — भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 250(अ)/18 एफ० बी० आई० डी० आर० ए० 73, तारीख 26 अप्रैल, 1973 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 1 च ख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा की थी कि उक्त आदेश के जारी होने की तारीख से ठीक पहले प्रवृत्त सभी संविदाएं, सम्पत्ति के हस्तांतरण पत्र, करार, समझौते, पंखाट, स्थायी आदेश या अन्य लिखतें (जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से सम्बन्ध दायित्वों से भिन्न हैं) जिसमें मेसर्स हिन्दुस्तान ट्रेडर्स लि० बंब० द्वारा (पूर्विक बड़ौदा) नामक औद्योगिक उपक्रम या ऐसे उपक्रम की स्थायी कोई कम्पनी एक पक्ष कार है या जो ऐसे उपक्रम या कम्पनी पर लागू है उक्त आदेश के जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक के लिए निम्नलिखित रहेंगे और उक्त तारीख से पूर्व उसके अधीन उपगत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि पर्यन्त निम्नलिखित रहेंगे।

और भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 261(अ) 18 एफ० बी० आई० डी० आर० ए० 74, तारीख 24 अप्रैल, 1974 और भूतपूर्व उद्योग और नागरिकपूर्ति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 173(अ) 18 आई० डी० आर० ए० 75, तारीख 9 अप्रैल, 1975 और सं० का० आ० 309(अ) 18 एफ० बी० आई० डी० आर० ए० 76, तारीख 22 अप्रैल, 1976 द्वारा, उक्त आदेश, 25 अप्रैल, 1977 तक की अवधि के लिए, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, बढ़ा दिया गया था।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि 11 मार्च, 1978 तक की और अवधि के लिए, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, बढ़ा दी जाए।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 ख ख की उपधारा (2) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त आदेश की प्रवृत्ति को 11 मार्च, 1978 तक की और प्रवृत्ति के लिए, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, बढ़ाती है।

[सं० एफ० 4/1/73—सी० यू० सी०]

अ० कु० बोष, अपर सचिव।

ERRATUM

In the Ministry of Industry (Department of Industrial Development), Order No. F. 13(25)/LP/74, dated the 14th February, 1977, published in the Gazette of India Extraordinary, Part II—Section 3—Sub-section (ii), dated the 14th February, 1977, under Issue No. 68 and S.O. 162(E) on page 507, the following correction is to be made in the English version:—

In the sixth line of the said order for the word "case" read the word "cess".

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 173] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 23, 1977 वैशाख 3, 1899

No. 173] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 23, 1977/VAISAKHA 3, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd April 1977

S.O. 299(E).—Whereas in pursuance of Resolution of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) No. V 17020/25/77-ME(PG), dated the 23rd April, 1977, a Commission has been set up to inquire into and report on various matters as set out in the terms of reference specified in the said Resolution,

And whereas the Central Government is of opinion that all the provisions of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), should be made applicable to the said Commission,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 11 of the said Act, the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Act shall apply to the said Commission

[No. V.17020/25/77-ME(PG)]

C. R. KRISHNAMURTHI, Jt. Secy.

